भारत सरकार **राज्य सभा**
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय **अतारांकित प्रश्न सं. 2447**
वाणिज्य विभाग

दिनांक 13 मार्च, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए
चीन से बढ़ता आयात और कार्यनीतिक व्यापार असंतुलन

2447 श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला:
क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि विनिर्माण और आयात प्रतिस्थापन लक्ष्यों की दिशा में प्रयास करने के बावजूद पिछले दशक के दौरान चीन से भारत का आयात लगातार बढ़ता गया है;
(ख) विगत पांच वर्षो के दौरान चिह्नित की गई प्रमुख उत्पाद श्रेणियों सहित चीन से किए गए आयात और चीन को किए गए निर्यात का वर्ष-वार परिमाण और मूल्य क्रमशः कितना-कितना है; और
(ग) ऐसे बढ़ते व्यापार असंतुलन के आर्थिक और कार्यनीतिक निहितार्थों का आकलन क्या है तथा घरेलू उद्योग को सुदृढ़ करने और आयात स्रोतों में विविधता लाने के लिए क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं?

उत्तर
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जितिन प्रसाद)

(क) से (ग): भारत का चीन से आयात वर्ष 2004-05 में 7.10 मिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर वर्ष 2013-14 में 51.03 मिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, जो 618.73% की वृद्धि दर्शाता है, जबकि वर्ष 2014-15 से 2024-25 की अवधि के दौरान यह 60.41 मिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 113.46 मिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, जो 87.81% की वृद्धि है। इसके अलावा, वर्तमान वित्त वर्ष (2025-26) के दौरान, भारत के चीन को निर्यात में वित्त वर्ष 2024-25 की इसी अवधि की तुलना में 38.31% (अप्रैल-जनवरी) की वृद्धि हुई है, जबकि इस अवधि में भारत का चीन से आयात केवल 13.82% बढ़ा है। इससे संकेत देता है कि समय के साथ चीन से भारत के आयात की वृद्धि धीमी हुई है, जबकि वर्तमान वित्त वर्ष (2025-26) में भारत का चीन को निर्यात आयात की तुलना में अधिक तेजी से बढ़ रहा है।

पिछले पांच वर्षों के दौरान चीन से भारत के आयात और चीन को निर्यात की वर्षवार मात्रा और मूल्य का विवरण वाणिज्य विभाग की वेबसाइटों क्रमश:
(https://tradestat.commerce.gov.in/meidb/country_wise_all_commodities_import और https://tradestat.commerce.gov.in/meidb/country_wise_all_commodities_export) पर देखा जा सकता है।

वैश्वीकरण के इस युग में, वैश्विक मूल्य श्रृंखलाएं अंतरराष्ट्रीय व्यापार के साथ-साथ विकास के अवसरों को निर्धारित करने में तेजी से प्रभावशाली हो गई हैं। चूँकि भारत वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं के साथ अधिकाधिक एकीकृत हो रहा है, सफल जीबीबी एकीकरण के लिए आयात उतना ही महत्वपूर्ण है जितना निर्यात।

भारत में पूंजीगत वस्तुओं, इंटरमिडिऐट वस्तुओं और कच्ची सामग्रियों जैसे एक्टीव फार्मास्युटिकल सामग्री, ऑटो कंपोनेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स और असेंबलीज, मोबाइल फोन पार्ट्स आदि की बढ़ती मांग के कारण चीन से भारत का आयात काफी बढ़ गया है; इन वस्तुओं का उपयोग परिसज्जित उत्पादों के निर्माण में किया जाता है, जिनका निर्यात भी भारत से किया जाता है। ये वस्तुएं भारत में तेजी से बढ़ते क्षेत्रों जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मा, दूरसंचार और बिजली की मांग को पूरा करने के लिए आयात की जाती हैं।

साथ ही, भारत सरकार घरेलू विनिर्माण क्षमता को मजबूत करने और आयात पर निर्भरता को कम करने के लिए उत्पादन से संबंद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना, मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान जैसी पहलों को आगे बढ़ा रही है।

भारत के विनिर्माण क्षेत्र को विश्व स्तर पर बढ़ावा देने के लिए दिनांक 25 सितंबर, 2014 को 'मेक इन इंडिया' पहल शुरू की गई थी। वर्तमान में, 'मेक इन इंडिया' 2.0 विभिन्न मंत्रालयों/विभागों और राज्य सरकारों के माध्यम से कार्यान्वित 27 क्षेत्रों पर फोकस करता है।

भारत के 'आत्मनिर्भर' बनने के विजन को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मास्यूटिकल्स, व्हाइट गुड्स, दूरसंचार और नेटवर्किंग उत्पाद, उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूल आदि जैसे 14 प्रमुख क्षेत्रों में 1.97 लाख करोड़ रुपये के वित्तीय परित्यय के साथ उत्पादन-संबंद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजनाएं शुरू की हैं, जहां आयात पर अत्यधिक निर्भरता है। इन योजनाओं के लिए सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले विनिर्माण इकोसिस्टम के विकास के लिए, सरकार ने 76,000 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय के साथ सेमीकॉन इंडिया कार्यक्रम को मंजूरी प्रदान की है।

'ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस' के तहत कई पहलें की गई हैं, जिनमें व्यापार सुधार कार्य योजना (बीआरएपी), बी-रेडी असेसमेंट, जन विश्वास और व्यवसायों और नागरिकों पर अनुपालन के बोझ को कम करना शामिल है।

देश में लॉजिस्टिक्स लागत को कम करने और लॉजिस्टिक्स दक्षता में सुधार करने के लिए राष्ट्रीय संभार तंत्र नीति और पीएम गति शक्ति का शुभारंभ किया गया है। पीएम गति शक्ति लोगों और वस्तुओं की सुगम आवाजाही के लिए बहुआयामी अवसंरचना के एकीकृत विकास में भी सहायक है।

राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर विकास कार्यक्रम (एनआईसीडीपी) एक परिवर्तनकारी पहल है जिसका उद्देश्य भारत में विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी विनिर्माण केंद्र बनाना है।

सरकार द्वारा की गई पहलों से आयात पर निर्भरता में कमी आई है। उदाहरण के लिए, मोबाइल फोन का आयात वर्ष 2014-15 में 48,609 करोड़ रुपये से घटकर वर्ष 2024-25 में 3,710 करोड़ रुपये हो गया है।

वहीं दूसरी ओर, मोबाइल फोन का निर्यात वर्ष 2014-15 में 1,566 करोड़ रुपये से बढ़कर वर्ष 2024-25 में 2,05,017 करोड़ रुपये से अधिक हो गया है।

वर्ष 2024-25 में, पिछले वर्ष की तुलना में कई क्षेत्रों में चीन से आयात में गिरावट देखी गई है। उदाहरण के लिए, उर्वरकों (61.4%) इसके बाद अवशिष्ट रसायन और संबद्ध उत्पादों (19.7%), लोह एंव इस्पात (10.3%), और कृत्रिम धागे (9.5%) के आयात में भारी गिरावट आई है।

सरकार भारतीय व्यापारिक प्रतिष्ठानों को वैकल्पिक आपूर्तिकर्ताओं की खोज करने और आपूर्ति श्रृंखलाओं में विविधता लाने के लिए प्रोत्साहित करती है ताकि आपूर्ति के एकल स्रोतों पर निर्भरता कम हो सके। सरकार ने प्रमुख आर्थिक साझेदारों के साथ व्यापार समझौते संपन्न किए हैं और इनसे आयात स्रोतों और निर्यात स्थलों में विविधता आने और भारतीय व्यवसायों को वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में एकीकृत करने की उम्मीद है।

इसके साथ ही, सरकार नियमित रूप से आयात में होने वाली वृद्धि की निगरानी करती है और उचित कार्रवाई करती है। इसके अलावा, व्यापार उपचार महानिदेशालय (डीजीटीआर) को अनुचित व्यापार परिपाटियों के विरुद्ध व्यापारिक उपचारात्मक कार्रवाई शुरू करने और उसकी सिफारिश करने की शक्ति प्रदान की गई है।

सरकार घरेलू उद्योगों की प्रतिस्पर्धात्मकता और मजबूती सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

****